Publication	**Dainik Bhaskar**	**Language**	Hindi
Edition	New Delhi	**Journalist**	Bureau
Date	06/08/2025	**Page no**	1
CCM	37.33		

Efforts to increase milk procurement by 50 percent in 5 years under White Revolution 2.0: Shah

सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक

श्वेत क्रांति 2.0 के तहत 5 सालों में दूध की खरीद को 50 फीसद बढ़ाने के प्रयासः शाह

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए मंत्रालय की पहलों पर सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में शाह ने कहा, 5 साल में देश में 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत अब तक 35,395 नई सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं, जिनमें 6,182 बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (एमपीएसीएस), 27,562 डेयरी और 1,651 मत्स्य सहकारी समितियां शामिल हैं। सहकारिता क्षेत्र, कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए 3 राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल), राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) का गठन किया गया है। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), डेयरी, मत्स्य, सहकारी बैंक, चीनी सहकारी समितियों और शासन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहल की हैं। सहकारी समितियों के नेतृत्व में श्वेत क्रांति 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में दूध की खरीद को 50% बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Dainik Jagran (Rashtriya)**	**Language**	Hindi
Edition	New Delhi	**Journalist**	Bureau
Date	06/08/2025	**Page no**	10
CCM	41.86		

Now small farmers will also be contracted for seeds: Amit Shah

अब छोटे किसानों से भी होगा बीज के लिए अनुबंध : अमित शाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा, मोदी सरकार की मंशा सहकारी समितियों को केवल सामाजिक संगठनों तक सीमित रखने की नहीं
- सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक में लिए गए कई बड़े निर्णय

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अब परंपरागत बीजों के संरक्षण के लिए छोटे किसानों से भी अनुबंध किया जाएगा, ताकि उन्हें भी इस प्रक्रिया से मुनाफा मिल सके। वह नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की मंशा सहकारी समितियों को केवल सामाजिक संगठनों तक सीमित रखने की नहीं है, बल्कि उन्हें व्यावसायिक और प्रतिस्पर्धी इकाइयों में बदलने की भी है। अगले पांच वर्षों में दो लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से अब तक 35,395 समितियां बन चुकी हैं। इनमें कृषि ऋण, डेरी, बीज और जैविक उत्पादों से जुड़ी समितियां भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय

अमित शाह। फाइल

बीज सहकारी समिति लिमिटेड बीजों के संरक्षण, संग्रहण एवं उत्पादन का कार्य कर रही है और अब छोटे किसान भी इससे सीधे जुड़ेंगे। शाह ने बताया कि भूमिहीन और पूंजीविहीन व्यक्तियों के लिए सहकारिता क्षेत्र ही सबसे बड़ा अवसर है। सरकार ने हाल के वर्षों में तीन बड़ी बहु राज्यीय सहकारी समितियां बनाई हैं। पहली जैविक उत्पादों के लिए, दूसरी बीज क्षेत्र के लिए और तीसरी निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए है। इनमें राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक लिमिटेड किसानों के जैविक उत्पादों की प्रमाणिकता और मार्केटिंग सुनिश्चित करती है, जबकि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में सहायता करती है। बैठक में अमित शाह ने समिति के सदस्यों से अपील की कि वे अपने-अपने राज्यों में डेरी क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए विशेष प्रयास करें। उन्होंने कहा कि 'श्वेत क्रांति 2.0' के तहत अगले पांच वर्षों में सहकारी समितियों के माध्यम से देश का 50 प्रतिशत दूध संग्रह करने का लक्ष्य है।

****

Downloaded from
SAMVAD